



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 463]
No. 463]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 1986/अश्विन 9, 1908
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1 1986/ASVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-मूतन परिवहन विभाग)

(पतन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1123(अ).—केन्द्र सरकार महानगरीय स्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए मुरगांव पतन के लिए न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पतन कर्मचारी (बाल शिक्षा भत्ता) (संगोषण) विनियम, 1986 का अनुमोदन करती है जो अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

2. यह विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

[फाइल नं. पी. डब्ल्यू./पी. ई. आर.-28/85-वि.-I]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुरगांव पतन स्यास

मुरगांव पतन कर्मचारी (बाल शिक्षा भत्ता) (संगोषण), विनियम, 1986

प्रमुख पतन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पतन का न्यासी मंडल मुरगांव पतन कर्मचारी (बच्चों का शैक्षणिक भत्ता) विनियम, 1974 का संगोषण करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. (i) ये विनियम मुरगांव पतन कर्मचारी (बाल शिक्षा भत्ता) विनियम, 1986 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मुरगांव पतन-स्यास कर्मचारी (बाल शिक्षा भत्ता) विनियम, 1974 के विनियम 4 के वर्तमान उप-विनियम (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा:—

“(iii) यह भत्ता उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जिनमें मण्डल का कर्मचारी अपने वैधानिक स्थान से हटाया जाने के कारण बच्चे के स्थान में को जाने के लिए मजबूर है और/अथवा उसको शैक्षणिक के स्थान में अतिरिक्त स्तर का स्कूल अथवा स्कूल नहीं है। मण्डल के कर्मचारी का

पति/पत्नी मण्डल की सेवा से बाहर सेवारत है और अपने नियोक्ता से बच्चों का शैक्षणिक भत्ता का हकदार है, तो हम विनियमों के प्रयोजन के लिए उसे मण्डल का कर्मचारी माना जाएगा।

3. मूल विनियम के विद्यमान विनियम-4 के उप-विनियम (iii) के बाद आने वाले "स्पष्टीकरण" के बाद आने वाले "स्पष्टीकरण, 'ए' को छोड़ दिया जाएगा।

4. मूल विनियम के विद्यमान उप-विनियम (iii) के नीचे आने वाले "स्पष्टीकरण" के बाद के साथ निम्नलिखित उप-विनियम सन्निविष्ट किया जाए।

(iv) भारतीय स्कूल को एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए "अपेक्षित स्तर" का स्कूल नहीं माना जाएगा और विलोमतः/इसी प्रकार, बच्चे को उसके अपने धर्म सिद्धांत किसी अन्य धर्म के संकाय द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल में जाने से रोका है, तो उसे अपेक्षित स्तर का स्कूल नहीं माना जाएगा। साथ ही, यदि कोई के कर्मचारी की भाषा से भिन्न भाषा के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई होती है, तो उसे अपेक्षित स्तर का स्कूल नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 :

किसी स्कूल को इसलिए अपेक्षित स्तर का स्कूल इस आधार पर नहीं माना जाएगा क्योंकि वह किसी विशिष्ट धर्मसिद्धांत के संकाय द्वारा चलाया जा रहा है। तथापि, यदि इस प्रकार के स्कूल में अनिवार्य रूप में धर्म को पढ़ाया जा रहा है जिसके कारण अन्य धर्म को पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण अन्य धर्म का स्कूल होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, तो इस स्कूल को अपेक्षित स्तर का स्कूल नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 :

बच्चों का शैक्षणिक भत्ता की ग्राह्यता का निर्णय स्कूल का स्तर अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर तथा पढ़ाई का माध्यम तथा जन्म से अथवा अपने के द्वारा कर्मचारी की मातृभाषा के संदर्भ में किया जाता है, न कि किसी विशिष्ट संस्था में किसी विशिष्ट विषय न होने के संदर्भ में। जिस स्थान पर कर्मचारी तैनात है, वहाँ के "अपेक्षित स्तर" के स्कूल में मण्डल के कर्मचारी के बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाता है और/अथवा रिक्त स्थान न होने के कारण कर्मचारी जहाँ बसा हुआ है अथवा किसी भी कारण और कर्मचारी के बच्चे को मजबूरन कर्मचारी के तैनाती स्थान और/अथवा निवास स्थान से दूर स्कूल में जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में कर्मचारी को भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि यह मान लिया जाएगा कि उस स्थान पर अपेक्षित स्तर का स्कूल है ही नहीं।

स्पष्टीकरण 3 :

स्कूल में रिक्त स्थान की उपलब्धता का निर्णय बच्चों के स्कूल में दाखिला के समय विद्यमान स्थिति के आधार पर किया जाएगा, चाहे वह सत्र के आरम्भ में हो या सत्र के मध्य में, उस क्षेत्र के सक्षम शिक्षा प्राधिकारियों से परामर्श कर की जाएगी, न कि स्कूल प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर। कर्मचारी के तैनाती स्थान और/अथवा आवास के पास अपेक्षित स्तर का स्कूल न होने अथवा इस प्रकार के स्कूल में रिक्त स्थान न होने के कारण जिन मामलों में बच्चों का शैक्षणिक भत्ते का दावा किया गया है। उस स्थिति में कार्यालय के अध्यक्ष का दावे की सहो स्थिति उन्हें सीधे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों से संपर्क कर समाधान कर देना होगा।

(v) जिस स्थान पर अपेक्षित स्तर का स्कूल नहीं है, उस स्थिति में भत्ते नहीं दिया जाएगा यदि पास में ही ऐसा स्कूल है, जहाँ बच्चों के लिए बस अथवा रेल गाड़ी की सुविधा है, जिससे बच्चों को स्कूल बस अथवा रेलगाड़ी से खुलने के समय और स्कूल चले जाने के बाद आवास तक पहुँचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और दोनों तरफ का सफर तय करने के लिए एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता है। जहाँ से भत्ते पूरा नहीं होनी है, वहाँ कर्मचारी के तैनाती स्थान और/अथवा आवास से स्कूल की दूरी का लिहाज लिए बिना भत्ता दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

अभिप्राय यह है कि बच्चों का शैक्षणिक भत्ता उन स्थितियों में कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जिसमें कि पास ही अपेक्षित स्तर का स्कूल है और बच्चा बस-रेलगाड़ी में आराम से स्कूल जा सकता है तथा बस/रेल गाड़ी की दोनों तरफ की यात्रा एक घंटे से अधिक नहीं है। ऊपर बताया गया एक घंटा बस/रेल गाड़ी द्वारा यात्रा करने के लिए लगने वाला समय है। अतः, सही कसौटी बस अथवा रेल द्वारा सफर करते में लगने वाला समय है, न कि आवास और स्कूल के बीच की दूरी। प्रत्येक मामले में दोनों तरफ की यात्रा के लिए एक घंटा अपनाए के लिए बताया गया है, किन्तु सत्र में कुछ बढ़ोतरी को वजित नहीं किया जा सकता है। इन प्रादेशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक मामले में अपने स्वविवेक से काम ले सकते हैं।

5. मूल विनियम के विनियम-4 के विद्यमान उप-विनियम (iii) के "स्पष्टीकरण-ए" के बाद आने वाले "नोट" को उप-विनियम (7) में बदल दिया जाए।

6. मूल विनियम के विनियम-4 के उप-विनियम (iv), (v), (vi), (vii), (viii) और (ix) को क्रमशः उप-विनियम (viii), (ix), (x), (xi), (xii) और (xiii) संख्या दी जाए।

7. विनियम-4 के विद्यमान उप-विनियम (iv) [जिसमें कि शब्द (x) की संख्या देने का प्रस्ताव है] में "हो कमन्ट्री" और "द्वारे सविड" शब्दों के बीच अन्तिम पंक्ति में आने वाले "तीन" शब्द का प्रतिस्थापन "एक" शब्द से किया जाए।

MINISTRY OF TRANSPORT (Department of Surface Transport) (Ports Wing)

New Delhi, the 1st October, 1986
NOTIFICATION

G.S.R. 1123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees' (Children's Education Allowance) (Amendment) Regulations, 1986 made by the Board of Trustees for the port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW/PER-28/85-PE-I]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

THE SCHEDULE

MORMUGAO PORT TRUST

MORMUGAO PORT EMPLOYEES (Children's Education Allowance) (Amendment) Regulations, 1986.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees' (Children's Education Allowance) Regulations, 1974, namely :—

1. (i) The Regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Children's Education Allowance) (Amendment) Regulations, 1986.

(ii) They shall come into force with effect from the date on which the Central Government's approval to these regulations has been published in the Gazette of India.

2. The following shall be substituted for the existing sub-regulation (iii) of regulation 4 of the Mormugao Port Employees' (Children's Education Allowance) Regulations, 1974, namely :—

“(iii) The allowance will be admissible only in those cases where an employee of the Board is compelled to send his child or children to a school away from the station at which he is posted and/or is residing owing to the absence of a school or schools of a requisite standard at that station. The wife/husband of the employee of the Board employed outside the Board's service and entitled to the benefit or Children Education Allowance from her/his employer shall be deemed to be an employee of the Board for this purpose of these Regulations”.

3. “EXPLANATION ‘A’” appearing after ‘EXPLANATION’ to sub-regulation (iii) of existing Regulation 4 of the principal Regulation shall be deleted.

4. After ‘EXPLANATION’ appearing below existing sub-regulation (iii) of existing Regulation 4 of the principal regulation the following sub-regulations shall be inserted.

(iv) An Indian School shall be held to be a School not of “requisite standard” for Anglo Indian children and vice-versa. Similarly, if a child is prevented by the

tenets of his religious persuasion, from attending a school run by a body of another persuasion such school shall be held to be a school not of the requisite standard. Also, if the teaching in a school is conducted in a language different from the language of the employee of the Board, the school shall be held to be a school not of the requisite standard.

Explanation 1 : A school cannot be treated as a school not of the requisite standard merely because it is run by a body of a particular religious persuasion. If, however, religious instructions are compulsorily imparted in such a school on account of which the child is prevented from attending the school being of a different religious persuasion, then that school can be treated as a school not of the requisite standard.

Explanation 2 : The admissibility of Children's Education Allowance will have to be determined with reference to the standard of school viz. Primary, Middle, High/Higher Secondary and the medium of instruction and mother tongue of the employee by birth or by adoption and not due to absence of particular subject in a particular institution.

(v) If a child of an employee of the Board is denied admission to a school of the “requisite standard” at the station at which the employee is posted and/or residing because of there being no vacancy, or for any other reason and the child is, therefore compelled to attend the School, away from the Employee's place of posting and/or residence the employee shall be entitled to the allowance as if there were no school of the requisite standard at that station.

Explanation : The availability of vacancy in a school will be determined with reference to the position existing at the time of the admission of the child in the school, whether it be at the start of the session or in the middle of the session, if in consultation with the competent Educational authorities of the area and not on the basis of the certificate of the school authorities. In cases where Children's Educational Allowance is claimed due to non-availability of a school of the requisite standard at the station of posting and/or

residence of the employee or due to non-availability of vacancy in such school the head of office should satisfy himself about the correctness of the claims and for this purpose, he shall obtain in the required information directly from the local educational authorities.

- (vi) At a station where there is no school of the requisite standard, the allowance will not be admissible if the nearest school is so situated that there is a convenient train or bus service to take the children near the time of the opening of the school and bring them back not too long after the school is closed and the journey each way does not take more than an hour. Where these conditions are not fulfilled, the allowance will be admissible irrespective of the distance of the school from the station at which the employee is posted and/or is residing.

Explanation : The intention is that Children's Educational Allowance will not be admissible to an employee even in a case where a school of the requisite standard exists in a nearby place where the child can conveniently attend the school by going in a train or bus and the train/bus journey does not take more than one

hour on either side. The period of one hour mentioned above only refers to the time taken by a train/bus to perform journey and not the time taken by a child to go on a bicycle or on foot. Hence, the real criteria is the time normally taken by bus or a train and not the distance between the place of residence and the school. While the limit of one hour on either side has been mentioned to be adopted in such cases, but marginal increases are not ruled out. The administrative authorities should in each case use their discretion keeping in view the spirit of these orders.

5. 'Note' appearing after "EXPLANATION 'A'" of existing sub-regulation (iii) of Regulation 4 of the principal Regulations should be lettered as sub-regulation (vii).

6. Existing sub-regulation (iv), (v), (vi), (vii), (viii) and (ix) of Regulation 4 of the principal Regulations shall be renumbered as sub-regulation (viii), (ix), (x), (xi), (xii) and (xiii).

7. In the existing sub-regulation (vi) of Regulation 4 [now proposed to be renumbered as (x)] the word "three" appearing in the last line between the words "he completes" and "years service" shall be substituted by the word "one".